प्रत्येक सोमवार को हल्द्वानी से प्रकाशित

RNI No.- UTTHIN/2017/73662

कुमाऊं जनसन्देश

www.kumaonjansandesh.com

वर्ष – 7 | अंक – 10 | हल्द्वानी(नैनीताल) | सोमवार 3 फरवरी 2025 | पृष्ठ – 4 | मूल्य – 1

12 लाख की सालाना आय पर अब आयकर नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश किया

हल्द्वानी/देहरादून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में रिकश्वर्ड आठवां लगातार बजट पेश किया। इस दौरान जैसे ही उन्होंने 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं दिए जाने की घोषणा की तो उत्तराखंड में भी नौकरीपेशा लोगों के चेहरे खिल उठे।

बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड के **वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल** अपने यमुना कालोनी स्थित अपने आवास पर चर्चा करते दिखे। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। **सीएम पुष्कर सिंह धामी** ने ट्वीट कर कहा, मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदशह्न और सशक्त नेतृत्व में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कहा कि निश्चित रूप से इस कल्याणकारी निर्णय से मध्यम वर्ग सहित देश के आम आदमी को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए धन्यवाद- प्रधानमंत्री जी को बधाई।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बजट ने आम व मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर की सीमा 12 लाख तक बढाकर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बजट में 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है, उत्तराखंड को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड में रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शारदा कॉरिडोर, मानसखंड केदार खंड जैसी योजनाएं पाइपलाइन में है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने होम स्टे के लिए मुद्रा लोन के तहत कर्ज देने का प्रावधान किया है, उसका भी राज्य की बहनों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य में पहले से पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना प्रचलन में है। उड़ान योजना में 120 नए एयरपोर्ट को इस योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया है, उत्तराखंड में गोचर सहित गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित अन्य एयरपोर्ट को विकास का मौका मिलने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इसका लाभ उत्तराखंड को इसलिए मिलेगा क्योंकि यहां 50: से अधिक क्षेत्र इस योजना में शामिल होने से बचा हुआ है।

सांसद अजय भट्ट ने विकासोन्मुखी केंद्रीय बजट को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि इस बार बजट में सालाना 12 लाख तक आय को कर मुक्त करते हुए मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। केंद्रीय बजट को हर वर्ग, हर क्षेत्र और जनकल्याण को समर्पित बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश जहां चौहमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है जिसमें बजट का सबसे बड़ा योगदान रहता है। आज पेश किए गए बजट में आम गरीब व्यक्ति, मध्य वगह्नय, व्यापारी, छात्र, युवा और महिला वर्ग को हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए बजट दिया गया है। कहा कि एक लाख प्रति माह की औसत आय पर कोई कर नहीं लगेगा जिससे मध्यम वर्ग परिवारों की आय, खपत और वृ) होगी, इसके अलावा वेतन भोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा केसीसी के माध्यम से 5 लाख तक लोन, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1. 7 करोड़ किसान लाभान्वित करने के साथ-साथ उड़ान योजना के तहत नई उड़ान शुरू करने के लक्ष्य सहित कई नए प्राविधान किए गए हैं। हर क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ देश के आर्थिक सुधारीकरण, समावेशी विकास और खेती किसानी, गरीब, इन सबके जीवन उ)ार के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने समावेशी बजट पेश किया है जो कि नए भारत की नई नींव रखेगा।

कालाढूंगी विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत ने बजट को मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने वाला, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने वाला और निजी निवेश को बढ़ावा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा बजट को देश की आर्थिक वृ) को मजबूती प्रदान करेगा। भगत ने कहा 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा बढ़ाकर एक लाख तक कर दी गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का शुभारंभ किया गया है जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से बड़ा कर पांच लाख कर दी गई है जिसका सीधा लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई है। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से शुल्क समाप्त किया गया है। बजट में गरीब, किसान, युवा, ग्रहणी एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाला बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया है।

हल्द्वानी शहर विधायक सुमित हृदयेश ने बजट में 12 लाख टैक्स मुक्त आय को चुनावी जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा मोदी सरकार का यह बजट सामाजिक न्याय विरोधी, आर्थिक समानता विरोधी होने के साथ ही समावेशी विकास के मामले में एक बड़ी निराशा लेकर आया है। अन्नदाता हताश, युवा निराश और मिडिल क्लास मायूस बस यही है पिछले एक दशक से बजट की कहानी।

विकसित और समृद्ध भारत का बजट : महाराज

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि केन्द्रीय बजट-2025 सकारात्मक, स्वागत योग्य और आम व्यक्ति का बजट है। केन्द्रीय बजट-2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ष्ये बजट एक विकसित एवं खुशहाल भारत का बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी के संकल्प का और एक नये ऊर्जावान युवा भारत के सपनों को साकार करने का बजट है। यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की इनकम तक वालों को इनकम टैक्स के दायरे बाहर करना आम आदमी को बड़ी राहत देगा और भारत को आगे लेकर जाएगा। महाराज ने कहा इस बजट के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में गरीब, युवा, किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं, यह स्वागत योग्य है। उन्होंने एक बेहतर बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।

राष्ट्रीय खेल : खो-खो में महाराष्ट्र का दबदबा कायम

हल्द्वानी। 38वें राष्ट्रीय खेल के पांचवें दिन खो-खो प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने अपना दबदबा कायम रखते हुए पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।

पुरुष वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र ने ओडिशा को 32-26 के स्कोर से हराया, वहीं महिला वर्ग में भी महाराष्ट्र ने ओडिशा को 31-28 से मात दी। बता दे कि 37वें राष्ट्रीय खेल में भी खो-खो के पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले महाराष्ट्र और ओडिशा के बीच ही खेले गए थे। पुरुषों की कांस्य पदक प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल और केरल के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों टीमों ने एक ही समय पर खेल समाप्त किया, जिसके चलते मुकाबला सडन डेथ में गया और दोनों टीमों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक प्रदान किया गया। महिला वर्ग के कांस्य पदक मैच में दिल्ली और कर्नाटक के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। यह मैच भी सडन डेथ में पहुंचा और अंततः दोनों टीमों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।

सम्पादकीय...

आसान नहीं आर्थिक चुनौतियों से पार पाना

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्ग को आयकर में राहत देकर जिस तरह खुशी प्रदान की, उससे बजट की सराहना स्वाभाविक है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता की बागडोर संभालने के समय ढाई लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इस बार इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया। इस टैक्स छूट से मध्य वर्ग की जेब में अतिरिक्त पैसा होगा और इसके चलते खपत बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, लेकिन कितना, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि टैक्स छूट से जनता के पास करीब एक लाख करोड़ रुपये ही आएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले सप्ताह जो नया आयकर विधेयक लाया जाएगा, वह मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट के मुकाबले कहीं अधिक सरल और स्पष्ट होगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे इनकम टैक्स एक्ट आपराधिक छवि से मुक्त होगा। यदि ऐसा होता है तो इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा और वह समय पर सही तरीके से टैक्स देने को प्रेरित होगी। बजट में सरकार अपनी नीतियों के जरिये भविष्य की रणनीति भी सामने रखती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा कि सरकार बजट के माध्यम से किसी बड़े बुनियादी बदलाव की ओर बढ़ रही है। यह जरूर है कि सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ गरीबी उन्मूलन की योजनाओं पर व्यय बढ़ा रही है। यह बढ़ा हुआ खर्च सही तरह तभी इस्तेमाल हो सकेगा, जब राज्य सरकारें केंद्र की सलाह पर काम करेंगी। —षि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम आदि क्षेत्र में केंद्र की नीतियों पर सही ढंग से अमल राज्यों के सक्रिय सहयोग से ही हो पाता है। इस मामले में डबल इंजन सरकारें अर्थात भाजपा शासित राज्य सरकारों को तो लाभ मिलता है, लेकिन कई बार गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र की नीतियों को लागू करने में अड़चन आती है। कभी-कभी ये राज्य सरकारें केंद्र का सहयोग भी नहीं करतीं। वे केंद्र से मिले पैसे का उपयोग अपने हिसाब से करने पर जोर देती हैं और यदि केंद्र आपत्ति जताता है तो राज्य केंद्र पर अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप मढ़ते हैं और यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। बजट से पहले आए आर्थिक सर्वे की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इस सर्वे ने कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि मेडिकल पेशेवरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने दस हजार मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी और ऐसे भी उपाय करने होंगे कि लोग सही पोषण लें और अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें, जैसा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था। आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया था कि उद्योगों को महंगी बिजली मिल रही है। यह ध्यान रहे कि गरीब तबके को मुफ्त या सस्ती बिजली देने के कारण भी उद्योगों को दी जाने वाली बिजली महंगी हो रही है। अधिकांश राज्यों के बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन इस सेक्टर को जिस श्रम सुधार की जरूरत है, उस पर कुछ नहीं कहा गया, जबकि आर्थिक सर्वे ने यह रेखांकित किया था कि भारत का श्रम बाजार मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से पार पाने में सक्षम नहीं। बजट में कौशल विकास पर जोर अवश्य दिया गया है, लेकिन क्या हम इसकी अनदेखी कर सकते हैं कि इस मामले में अभी तक के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं? बेहतर होता कि सरकार ऐसी किसी रणनीति के साथ सामने आती कि कुशल श्रमिकों की कमी सचमुच दूर होती। सरकार को चाहिए था कि बजट के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को कौशल विकास की योजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती। आखिर सरकार ने कौशल विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर ही क्यों नहीं डाली।

इसी तरह उसे गिग वर्करों के कल्याण की जिम्मेदारी भी कंपनियों पर डालनी चाहिए थी। इसलिए और भी, क्योंकि आर्थिक सर्वे कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अपने बढ़े हुए मुनाफे के अनुरूप वेतन नहीं दे रहा है। अर्थव्यवस्था को बल शहरी क्षेत्रों से मिलता है, लेकिन हमारे शहरी क्षेत्र खस्ताहाल हैं। इसका कारण नगर निकायों की खराब कार्यप्रणाली है। राज्य सरकारें इस कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए तत्पर नहीं। इसी कारण केंद्र सरकार शहरों की सूरत संवारने के लिए जो धन देती है, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। इस बार बजट में शहरी ढांचे को सुधारने और शहरों के विकास को लेकर किसी ठोस योजना का अभाव दिख रहा है। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार राज्यों से मिलकर शहरों की सूरत संवारने के लिए कोई ठोस नीति लेकर आए और उस पर अमल भी कराए, क्योंकि हमारे शहर ही अर्थव्यवस्था का इंजन बनेंगे। बजट यह संकेत दे रहा है कि सरकार देश में जो आर्थिक सुस्ती दिख रही है, उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। वह इसमें सफल हो सकती है, क्योंकि आयकर में छूट देने के साथ उसने कुछ समय पहले आठवें वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा की है, लेकिन इसमें संदेह कि बजट उन चुनौतियों का समाधान करने में भी सक्षम होगा, जो विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में आड़े आ रही हैं। बजट यह संकेत नहीं करता कि सरकार चीन की ओर से पेश की जा रही आर्थिक चुनौती का सामना करने को तत्पर है। यह तब है, जब चीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

जलाशयों व नदियों की सफाई की बनाएं कार्ययोजना : डीएम

जिलाधिकारी भदौरिया ने ली आपदा प्रबंधन पूर्व तैयारियों की बैठक

रुद्रपुर। आपदा प्रबंधन पूर्व तैयारियों की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि वर्षाकाल में जनपद के कई क्षेत्रों में जलाशयों व नदियों के रास्ता बदलने से जलभराव, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसलिए जलाशयों व नदियों की ड्रेजिंग द्धडी-सिल्टिंगऋ आवश्यक है। उन्होने हरिपुरा, बैगुल, तुमड़िया, धौरा व शारदा जलाशयों का डी-सिल्टिंग किया जाना है इस हेतु उन्होने सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता सिंचाई, उप निदेशक खनन, उप प्रभागीय वनाधिकारी व तहसीलदार की समिति गठित करते हुए जलाशयों में सिल्ट का सर्वे मूल्यांकन करते हुए 10 दिन में रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। अधीक्षण अभियंता सिंचाई पीके दीक्षित ने बताया कि हरिपुरा जलाशय व बौर जलाशय की जल संचय क्षमता सिल्ट के कारण आधी रह गयी है। हरिपुरा व बौर जलाशय एक साथ जुड़े हुए है। हरिपुरा जलाशय में पानी पहाड़ो की ओर से आता है इसलिए सिल्ट हरिपुरा जलाशय में जमा हो जाती है। क्योकि बौर जलाशय, हरिपुरा जलाशय के डाउन स्टीम मे है इसलिए उसमे सिल्ट कम आता है। उन्होने कहा कि हरिपुरा जलाशय की डी-सिल्टिंग कराना अतिआवश्यक है। इसी तरह तुमड़िया जलाशय की भी डी सिल्टिंग आवश्यक है। जिस पर जिलाधिकारी ने आपदा न्यूनीकरण पूर्व कार्य हेतु जलाशयों की डी-सिल्टिंग कार्य अतिआवश्यक है, इसलिए सर्वे कर 10 दिन के अन्दर आख्या प्रस्तुत करें। बैठक में सीडीओ मनीष कुमार, डीएफओ यूसी तिवारी, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, ओसी खनन मनीष बिष्ट, उप जिलाधिकारी रविन्द्र जुआठा, उप निदेशक खनन अमित गौरव, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी मौजूद थे।

लम्बित वादों के निस्तारण में लाएं तेजी

रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शुक्रवार को जिला सभागार में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए लम्बित वादों को त्वरित निस्तारण करने व राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए न्यायालयों में अभियोजन पक्ष द्वारा पैरवी प्रभावी तरीके से रखने के निर्देश दिये ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। उन्होने कहा कि कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी समन्वय बनाकर समय-समय पर रात्रि के समय क्षेत्रों में भ्रमण भी करें। उन्होने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला अपराध को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उप जिलाधिकारी, एआरटीओ व पुलिस क्षेत्राधिकारी दुर्घटना स्थल चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों के साथ समन्वय स्थापित कर आरसी का मिलान करते हुये वसूली को बढ़ाये व बड़े बकायेदारों से सूची बनाते हुए तहसीलो में लगायी जाये व सख्ती से वसूली की जाये। उन्होने जिन अमीनो द्वारा राजस्व वसूली में ढीलाई बरती जा रही है उनका वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होने उप निदेशक खनन को निर्देश दिये कि जो मिट्टी खनन की अनुमति दी जाती है उसकी सूचना सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को भी अवश्य दे व खनन क्षेत्र का सीमांकन उप जिलाधिरी के नेतृत्व में किया जाये। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली लक्ष्य को समय से पूर्ण करें। उन्होंने आबकारी अधिकारी को कच्ची शराव व अवैध मदिरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिये। उन्होने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि बैंको के आरसी देयको की वसूली की जाये तथा वसूली चार्ज भी जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होने सीएम हैल्पलाईन, सीएम जन समर्पण पोर्टल में प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुये समय से निस्तारण करें व शिकायतकर्ता से स्वयं वार्ता भी करें। उन्होने आयोग के सन्दर्भो, आडिट आपत्तियो, मजिस्ट्रीय जांच को भी प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियो को दिये। जिलाधिकारी ने ई-वाहनो के चार्जिगं के लिए चार्जिग स्थल चयनित करने हेतु समिति गठित करते हुए स्थल चयन करने के निर्देश दिये।

अल्मोड़ा में 39 नालों की टैपिंग की आवश्यकता

अल्मोड़ा। जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला परियोजना अधिकारी रंजीता ने बताया कि जनपद में 39 नालों की टैपिंग आवश्यक है जिसके क्रम में जिलाधिकारी ने पेयजल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि फरवरी माह में प्रदूषित नालों की सूची तैयार कर ली जाय। उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बख स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट में फिल्टरेशन क्षमता को बढाया जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी को जिला गंगा समिति की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि बेस अस्पताल का बायो सश्वलिड वेस्ट एवं उसके आसपास खुले में कूड़ा फैला रहता है जो व्यक्तियों, बन्दरों, जानवरों को प्रभावित कर रहा है, इसका शीघ्र निस्तारण किया जाय। जिलाधिकारी ने गंगा सुरक्षा समिति से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो भी सूचना मश्वगी जाती है उसे ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आरसी पंत समेत अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

सम्पादक : विनोद चन्द्र पनेरू
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक विनोद चन्द्र पनेरू द्वारा भीड़ापानी-ओखलकांडा प्रिन्टिंग प्रेस(मोती सिंह), भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी(नैनीताल) से मुद्रित तथा हरिपुर लालमणि पो.ऑ- देवलचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखंड) से प्रकाशित। मो. 9410354318 Email:-vinodpaneru123@gmail.com

शारदा कोरिडोर के कार्यों में लाएं तेजी

नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में बैठक लेते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से शारदा कोरिडोर परियोजना संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शारदा कोरिडोर के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे किया जाए।

शारदा कोरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेनदशील क्षेत्र की स्टडी कर उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य किये जाएं। इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जायेगा। जिसमें नदी किनारे घाटों का सौन्दयह्नकरण, पर्यटकों और श्र)ालुओं के अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा और गंगा कोरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्र)ालुओं को सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं में अलग-अलग डिजाइन पर कार्य किये जायेंगे। शारदा कोरिडोर के तहत बुनियादी ढ़ांचे, पर्यटन और लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने से संबधित अनेक कार्य किये जायेंगे। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा एवं सबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

स्वच्छ व सुन्दर बनेगा उधमसिंहनगर

रुद्रपुर। जनपद को पर्यटन मंत्रालय व पेयजल एवं स्वच्छता जलापूर्ति मंत्रालय भारत सरकार के गाईड लाइन के अनुसार स्वच्छ व सुन्दर बनाया जायेगा। यह बात जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय स्वच्छता ग्रीन लीफ टेस्टिंग समिति की बैठक लेते हुए कही। जिलाधिकारी ने कहा पर्यटन एवं पेयजल स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकारी स्वच्छता ग्रीन लीफ टेस्टिंग प्रणाली के अन्तर्गत शहरों व ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णतः सफाई व स्वच्छता बनाये रखने हेतु प्रथम चरण में तहसील व ग्राम स्तर पर समितियां गठित कर जन जागरूकता किया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत शहरों व ग्रामीण स्तर पर होम स्टे, होटल, धर्मशालाओं व ग्रामों में अतिथि सुविधाओं के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा विकसित करना, अच्छी शौचालय सुविधा, स्वच्छ जल प्रबंधन, फीकल, स्लज प्रबंधन और ठोस कचरा तथा जल पुर्नचक्रण आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है। आतिथ्य सुविधाओं की सूची और मानचित्रण कर पर्यटन विभाग अथवा गठित समिति द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन कर स्वच्छता, सफाई व हाउसकीपिंग कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके उपरांत होटल, लॉज, होम स्टे, धर्मशाला, शिविर शौचालय का स्वंय संस्थान द्वारा स्वैच्छिक मूल्यांकन कर घोषणा प्रस्तुत की जायेगी तब स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग समिति द्वारा संस्थान का सत्यापन, मूल्यांकन किया जायेगा व सर्वेक्षण मूल्यांकन के आधार रेटिंग समिति द्वारा संस्थानों का प्रमाणन कर संस्थानों को रेटिंग (अंक) प्रमाण पत्र दिये जायेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य सड़को के किनारे कूड़ामुक्त करने हेतु सभी निकायों, लोनिवि, एनएच, राजस्व अधिकारियों को टीम बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य सड़क मार्गो में जहां गन्दगी, कूड़ा है को चिन्हित करते हुए 10-10 किमी के पैच बनाते हुए सफाई अभियान चलाया जाये। बैठक में सीडीओ मनीष कुमार, डीएफओ यूसी तिवारी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, एसडीएम रविन्द्र जुआठा, एसीएमओ डा. राजेश आर्या, जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट, डीपीओ मुकुल चौधरी आदि मौजूद थे।

बजट में किसानों की आय दोगुना करने को रोडमेप नहीं: आर्य

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 आम लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किए बिना बड़े-बड़े वादों का एक और प्रयास है। बड़े-बड़े दावों के विपरीत, जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है।बेरोजगारी और मुद्रास्फीति घरेलू आय को कम कर रही है। ग्रामीण संकट गहराता जा रहा है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए परिवर्तनकारी नीतियों की पेशकश करने के बजाय, बजट उन लाखों नागरिकों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज करता है जो सार्वजनिक सेवाओं पर निर्भर हैं। आर्य ने कहा कि बजट 2025 एक सुव्यवस्थित आर्थिक योजना के बजाय मात्र चुनावी घोषणा-पत्र बनकर रह गया है।बजट में युवाओं और किसानों को कोई वास्तविक राहत नहीं, बेरोजगारी और महंगाई पर ठोस समाधान की बजाय सतही दावे, एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनरेगा की उपेक्षा जारी है।स्मार्ट सिटी, मेडिकल कश्वलेज जैसी पुरानी घोषणाओं का कोई हिसाब नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि लोन माफी पर सरकार की चुप्पी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं, बस खोखले वादे हैं। कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए कोई रोडमेप नहीं, खेती के सामान पर जीएसटी दर में कोई रियायत नहीं दी गई। आसमान छूती महंगाई के बावजूद मनरेगा का बजट वहीं का वहीं है। श्रमिकों को आय बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया गया। बेरोजगारी को कम करने के लिए नौकरियां बढ़ाने की कोई बात नहीं की।स्टार्ट अप इंडिया, स्टेण्ड अप इन्डिया, स्किल इंडिया सभी योजनाएं बस घोषणाएं साबित हुई। कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत करने की जरूरत थी, लेकिन बजट में 1,255 करोड़ की कटौती कर दी गई। यह सरकारी अस्पतालों, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और नई स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार को प्रभावित कर सकता है। आर्य ने कहा कि शिक्षा बजट में 11,584 करोड़ की कटौती भारत के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। जब भारत को नई शिक्षा नीति (नैप) को प्रभावी ढंग से लागू करने और उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ाने की जरूरत थी, तब इस कटौती से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि बजट में 10,992 करोड़ और ग्रामीण विकास में 75,133 करोड़ की कटौती से किसानों और ग्रामीण गरीबों को बड़ा झटका लगेगा।

डीएम ने की सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा

बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश

पिथौरागढ़। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता मे शनिवार को जिला कार्यालय सभागार में पीएमजीएसवाई के तहत निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई के सभी खण्डों के फेज 1 ,फेज 2 तथा फेज 3 के अंतर्गत कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा पीएमजीएसवाई से जनपद में सड़कों की जियो टैगिंग तथा मैप के माध्यम से जानकारी ली गई। उन्होंने पीएमजीएसवाई के सभी खण्डों से उनके कार्यों की विस्तृत जानकारी ली जिसमें एनपीसीसी,ब्रिडकुल, सिंचाई खंड 1 पीआईयू 1, पीआईयू 2, पीआईयू 3, पीएमजीएसवाई धारचूला खंड आदि से निर्माण कार्यों की जानकारी ली गई।

बैठक में विधानसभा डीडीहाट के विकासखंड कनालीछीना के अंतर्गत ओगला भागीचौरा पस्मा हंसेश्वर मोटर मार्ग द्धअपग्रेडेशनऋ, जौलजीबी झुलाघाट मोटर मार्ग, नारायण नगर अस्कोट मोटर मार्ग, मुनाकोट के अंतर्गत बढ़ावे तोली शिलिंगिया मोटर मार्ग, मुनाकोट बढ़ावे धारी बेलतड़ी से क्वारबम मोटर मार्ग में 48 मी स्पान सेतु निर्माण, गंगोलीहाट के दशाईथल खीरमाड़े ग्वासिकोट मोटर मार्ग सहित अन्य सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पलायन रोकने हेतु सड़कों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है इसलिए जिन सड़कों का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण होना है उनमें वर्षाकाल से पूर्व कटिंग का कार्य तथा डामरीकरण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा की जनपद के सड़कों की जिओ मैपिंग के अध्ययन हेतु जीआईएस एक्सपर्ट को भी जनपद में बुलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने एस.सी पीएमजीएसवाई को निर्देशित किया कि वह पीएमजीएसवाई के सभी खण्डों के अंतर्गत सभी फेज की योजनाओं की विस्तृत जानकारी जिनमें पूर्ण हुए कार्य, लंबित कार्य तथा लंबित होने का कारण आदि जानकारी दो से तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराएंगे जिससे यह जानकारी सुशासन पोर्टल पर अंकित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने सुशासन पोर्टल पर पीएमजीएसवाई से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की गई उन्होंने निर्देशित किया कि सुशासन पोर्टल पर पंजी□त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा जिन शिकायतों का निस्तारण हो चुका है उनसे संबंधित जवाब पोर्टल पर 15 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ जिलाधिकारी द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पीएमजेएसवाई के कार्यों में लक्ष्य के सापेक्ष कम कार्य होने पर एस.सी पीएसमजीएसवाई को निर्देशित किया की 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र लंबित कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डा. दीपक सैनी, एस.सी पीएमजीएसवाई एम. एस यादव, एएई पीएमजीएसवाई धारचूला विपिन करनवाल, एई दौलत चंद्र पीएमजीएसवाई सिंचाई खंड, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कुलपति ने शोध की प्रगति पर दिया प्रस्तुतिकरण

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के समक्ष उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.दिनेश चन्द्र शास्त्री ने राजभवन में 'वन यूनिवर्सिटी-वन रिसर्च' के अंतर्गत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया। उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा ''संस्कृति और भारतीय ज्ञान प्रणाली की पुनर्स्थापना: उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में'' विषय पर शोध किया जा रहा है। प्रो.शास्त्री ने शोध के उद्देश्य और प्रमुख निष्कर्षों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय ज्ञान प्रणाली और संस्कृति के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। शोध के माध्यम से तीर्थाटन और पर्यटन के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अंतर की अज्ञानता के कारण पवित्र तीर्थ स्थलों की शुचिता प्रभावित हो रही है, जिससे पर्यावरणीय, सामाजिक और प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में केवल पांच प्रयाग(संगम) होने की आम धारणा है।शोध के दौरान शास्त्रों के गहन अध्ययन से यहां इससे अधिक प्रयागों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि यदि इन प्रयागों का प्राचीन शास्त्रों के आधार पर प्रचार-प्रसार किया जाए, तो इससे उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और अधिक बल मिलेगा। इससे तीर्थाटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोत्तरी होगी। राज्यपाल ने इस महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए शोधकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह अध्ययन हमारी प्राचीन ज्ञान प्रणाली और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में सहायक होगा। उन्होंने इस शोध कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इसके अंतिम निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जा सके।

पीरूमदारा में अब शहरी मानक के आधार पर मिलेगा पानी

जल निगम ने प्री-अर्बन श्रेणी में किया शामिल

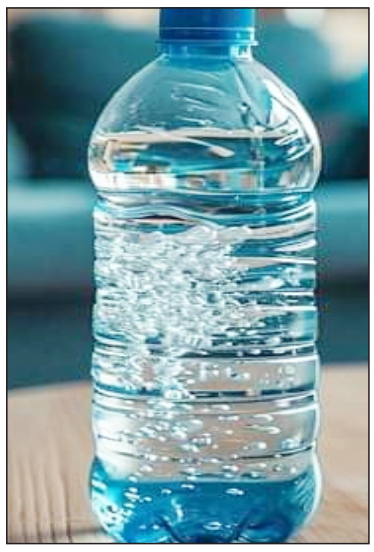

रामनगर। रामनगर से सटे पीरूमदारा गांव के लोगों के लिए खुशखबरी है। जल निगम ने पीरूमदारा में पानी की कमी को दूर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए निगम ने पीरूमदारा गांव को प्री-अर्बन गांव की श्रेणी में शामिल किया है। ग्राम पीरूमदारा में 1500 से अधिक पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं। पीरूमदारा के गांव की श्रेणी में होने से यहां प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रति दिन द्धएलपीडीक्ष पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। जल निगम के अधिकारियों ने बढ़ती पानी की डिमांड को पूरा करने के लिए पीरूमदारा को प्री-अर्बन की लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। भौतिक निरीक्षण के बाद उच्चाधिकारियों ने पीरूमदारा को प्री-अर्बन की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब निगम यहां के लोगों को प्रति व्यक्ति 135 एलपीडी पानी उपलब्ध कराएगा। इससे स्थानीय लोगों को सहूलियत मिलेगी। जल निगम के अधिकारियों के अनुसार पीरूमदारा के प्री-अर्बन श्रेणी में आने के बाद नई योजनाएं 135 एलपीडी के आधार पर बनाई जाएंगी। इसके लिए निगम ने कई योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिए हैं।

अधिशासी अभियंता, जल निगम रामनगर पल्लवी चौधरी के अनुसार, पीरूमदारा को प्री-अर्बन गांव की श्रेणी में शामिल किया है। अब यहां के लोगों को शहरी मानक की तरह पानी की आपूर्ति की जाएगी। वहीं, बेतालघाट ब्लश्वक के डोबा गांव में तीन महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को पेयजल निगम के कर्मचारी गांव में पेयजल व्यवस्था सुचारु करने के लिए पाइप लाइन की मरम्मत करने में लगे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके चलते ग्रामीणों को जलस्रोतों से पानी भरने को मजबूर होना पड़ा। पेयजल निगम रामनगर के जेई नरेंद्र भारती ने बताया कि क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को सही किया जा रहा है। साथ ही गांव को जाने वाली लाइन की जांच भी की जा रही है, जल्द ही पानी की सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। इधर, नव सांस्कृतिक सत्संग समिति रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट अश्वफ हिमालयन एनवायरनमेंट संस्था कोसी कटारमल अल्मोड़ा की ओर से देहरादून से आई टीम के माध्यम से लोगों को पानी की उपयोगिता और महत्व की जानकारी दी गई। उन्होंने जल संचय के लिए लोगों को प्रेरित किया। नवनियुक्त सभासद जीनू पांडे की पहल पर हुए कार्यक्रम में डश्व. मधुवेन शर्मा ने कहा कि वह नैनीताल जिले में स्थित झरनों, नदी, तालाब व स्रोत के पानी की जांच करने आई हैं। इस दौरान बच्चों की कला प्रतियोगिता भी की गई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वहां प्रो. ललित तिवारी, सभासद रमेश प्रसाद, दिनेश जोशी, हरीश पाठक, गौरव जोशी, इंद्र सिंह रावत, कैलाश जोशी आदि थे।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 36 इकाइयों को भेजे नोटिस

पिथौरागढ़-बागेश्वर की तीन-तीन, चंपावत की पांच यूनिट शामिल

हल्द्वानी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली 36 इकाइयों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनके जरिये पहाड़ से लेकर मैदान तक वातावरण को दूषित करने का काम किया जा रहा था। इसमें 29 तो स्टोन क्रसर हैं, जबकि शेष सात पल्वराईजर द्धचक्कीक्ष हैं। इन सभी से एक माह के अंदर जवाब मांगा गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र के 18 स्टोन क्रशर इकाइयों को नोटिस जारी कर पूछा है कि नियमों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। जब क्रशर के समय पानी का छिड़काव जरूरी है और इसे हर हाल में ढककर रखना होता है, तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी क्रम में पिथौरागढ़ के तीन स्टोन क्रशर इकाइयों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बागेश्वर की तीन इकाइयों के साथ ही चंपावत जनपद की पांच इकाई को भी नोटिस जारी हो चुका है। अब विभाग को इन सभी के जवाब का इंतजार है। यदि तय समय में जवाब नहीं मिला तो विभाग अगली कार्रवाई के रूप में जुर्माना डाल सकता है। उधर जनपद के कुल सात पल्वराईजर इकाइयों को भी नोटिस जारी करते हुए पर्यावरण को दूषित करने पर जवाब मांगा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तय मानक का पालन न करने पर भी जवाब मांगा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने कहा कि कुमाऊं मंडल के चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हल्द्वानी, नैनीताल और लालकुआं की 36 इकाइयों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्रदूषण को नुकसान पहुंचाने वाले कारक बर्दाश्त नहीं होंगे। इनके जवाब मिलने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

हल्द्वानी से हर दिन महाकुंभ में पहुंच रहे एक हजार से अधिक लोग

कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग जा रहे प्रयागराज

महाकुंभ को लेकर दस जनवरी से हल्द्वानी डिपो ने चलाई हैं तीन बसें

हल्द्वानी। प्रयागराज महाकुंभ में देश से ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर दस जनवरी से हल्द्वानी डिपो ने तीन बसे चलाई हैं। इसमें औसतन हर दिन करीब दो सौ लोग यात्रा कर रहे। टूर ट्रेवलर से मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस, टैक्सी से रोजाना पांच सौ लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। वहीं अपने वाहनों से औसतन तीन सौ लोगों प्रयागराज जाने का अनुमान है। उत्तराखंड परिवहन निगम हल्द्वानी डिपो ने महाकुंभ के लिए दस जनवरी से अब तक तीन स्पेशल बसें चलाई हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बसों की संख्या भी बढ़ाई भी जा रही हैं। विभाग से मिले आकड़ों के अनुसार औसतन करीब दो सौ से अधिक लोग प्रतिदिन रोडवेज की बसों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इससे डिपो को काफी मुनाफा हो रहा हैं। साधारण बस से एक फेरा पूरा करने में करीब 70-80 हजार तो वश्वल्वो से करीब डेढ़ लाख से अधिक की कमाई हो रही है। कम खर्च में महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों के लिए रोडवेज बसें बेहतर साबित हो रही हैं। हल्द्वानी डिपो के एआरएम संजय पांडे ने बताया कि महाकुंभ की शुरुआत से तीन बसें रोजाना प्रयागराज भेजी रही हैं। इसमें एक साधारण, दो वॉल्वो बस हैं। बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी लगाई जा रही हैं। प्रयागराज में लगे महाकुंभ के प्रति लोगों की आस्था काफी बढ़ी है। शहर से लेकर पहाड़ों से लोग महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। कुमाऊं के महानगर हल्द्वानी से रोजाना बड़ी संख्या में लोग रोडवेज बस के अलावा प्राइवेट बसों, टेंपो ट्रेवलर से प्रयाग जा रहे हैं। टूर ट्रेवलर कारोबारी हरित कपूर ने बताया कि हल्द्वानी से प्राइवेट बसों, टेंपो ट्रेवलर और टैक्सी से रोजाना करीब पांच सौ से अधिक लोग प्रयागराज महाकुंभ के लिए यात्रा कर रहे हैं। बताया कि कुछ दिन पूर्व महाकुंभ में हुए हादसे के चलते कई बसों की बुकिंग कैंसिल हुई हैं। तब भी प्रतिदिन करीब दस से 15 प्राइवेट बसे रोजाना महाकुंभ के लिए जा रही हैं।

रामनगर के तीन रेंजों में पूरी हुई बाघों की गणना

दो लाख से अधिक खींची तस्वीरें, जल्द आंकड़े होंगे जारी

रामनगर। कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग ने फेस-4 विधि से बाघों की गणना का कार्य शुरू कर दिया है। तीन रेंजों में बाघों की गणना का कार्य पूरा हो चुका है। एक फरवरी से कालाढूंगी और फतेहपुर रेंज में गणना के लिए इन दिनों कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य किया जा रहा है। मार्च अंत तक गणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद बाघों की गणना के आंकड़े जारी किए जाएंगे।

रामनगर वन प्रभाग का क्षेत्रफल करीब 50 हजार हेक्टेयर है। वर्ष 2022 में हुई एनटीसीए की गणना में 67 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। डीएफओ दिगंथ नायक ने बताया कि अब तक रिजर्व पार्कों की तरह ही पिछले महीने फेस-4 विधि से गणना का कार्य शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि रामनगर वन प्रभाग की तीन रेंज कोटा, देचौरी और कोसी रेंज में बाघों की गणना का कार्य पूरा हो गया है। बाघों की गणना के लिए तीनों रेंजों में 250 कैमरा ट्रैप लगाए गए थे, जिसमें कैमरा ट्रैप ने बाघों की दो लाख से अधिक तस्वीरें खींची हैं। बताया कि अन्य दो रेंज फतेहपुर और कालाढूंगी में एक फरवरी से 150 कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। डीएफओ दिंगथ नायक ने बताया कि अब तक पूरी हुई गणना में कुछ नए बाघ भी देखे गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 67 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। इस साल हो रही बाघों की गणना से बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।